

न्यायिक सक्रियता Judicial Activism

फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी एवं दार्शनिक ले मॉण्टेस्क्यू (Montesquieu) ने अपनी पुस्तक "Spirit of Law" में शासन के तीनों अंगों की शक्तियों का वर्णन किया। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के शक्तियों के पृथक्करण का विचार प्रस्तुत किया।

उसके अनुसार शक्तियों के पृथक्करण के बिना न तो जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है न ही शासकीय अंगों की निरंकुशता बच पायेगी। किसी एक व्यक्ति या निरुपेक्ष को सौंप देने पर सब नष्ट हो जायेगा। सभी अंगों का अपना-अपना क्षेत्र सुनिश्चित हो तथा अपने-अपने कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न करें। यदि विधायिका व कार्यपालिका अपने कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं कर पाती तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। यही सक्रियता का जन्म होता है।

अर्थात् न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की गई वह सक्रिय भूमिका है जिसे शासन के अंगों को उनके संवैधानिक कृत्य करने के लिए बाध्य करें।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा लोकतंत्र के समग्र प्रदरी के रूप में अभिव्यक्त होती है जिसे न्यायालय के ~~केवल~~ की सहायक भूमिका बढ़ जाती है।

न्यायिक सक्रियता के विकास के कारण

- 1- कार्यपालिका व विधायिका की जनसमस्याओं के प्रति निष्क्रियता।
- 2- कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में लचील तर्कों को इतना।
- 3- संवेदनशील मुद्दों पर विधायिका व कार्यपालिका द्वारा निर्णय न लेना।
- 4- अनु० 32, 226 में न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति (226- उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति)
- 5- 39-A - निःशुल्क कानूनी सहायता या निर्णय को न्याय सुलभ करना।
(समान-मात्र एवं निःशुल्क विधायिका)

न्यायिक सक्रियता के पहलू-

- 1- जनहित प्रार्थिका (PIL - Public Interest Litigation)
- 2- अनु० 21 का विस्तार
- 3- कार्यपालिका के स्वविवेक पर निर्णय
- 4- पूर्ण न्याय
- 5- आध्यात्मिक दायें का निर्माण

जनहित याचिका (PIL) : Public Interest Litigation

जनहित याचिका की शुरुआत - याचकर्ता P.N. Bhagwati को जाता है। (17/03/85)

जनहित याचिका के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या समुदाय, जिसे कोई विधिक क्षति पहुंचाई गई हो या जिसके अधिकारों का हनन किया गया हो, परन्तु वह व्यक्ति निरर्थकता की वजह से न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीठ पर उसकी ओर से PIL कर सकता है।

PIL का उद्देश्य समाज के कमजोर तबके को न्याय प्राप्ति में मदद करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका (PIL) प्रस्तुत कर सकते हैं।

1- इस्तेन आरा घातून बनाम बिहार सरकार (1980) : बिहार जेलों में बंद विचारधर्मी कैदियों की दमनीय दशा को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया। जिसे अनुच्छेद 32 के तहत SC की वरिष्ठ वकील ~~कविता~~ श्रीमती पुष्पा कपिला हिगोरानी ने PIL दाखिल किया। भागलपुर जेल में बंद कैदियों को मुक्त कराया। ऐसे मामलों में जन्म सुनवाई का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग है।

2) सुची शीला वरसे (1983) : मुम्बई पुलिस की जेलों में बंद महिला कैदियों का मामला न्यायालय ने आदेश दिया कि महिला कैदियों को अलग ब्लॉक-धन में रखे जायें। उनकी सुझा की जिम्मेदारी महिला पुलिस को।

3) बंध्यना मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय संघ (1984) : एक स्वयंसेवी संस्था ने SC को सूचित किया कि फरीदकोट जिले में पत्थर की खानों में काफी संख्या में श्रमिक अनजानबीध दशा में मजदूरी कर रहे हैं तथा उनसे ज्यादा बंध्यना मजदूर हैं। न्यायालय ने उनके पत्र को रिट मानकर एक आयोग नियुक्त किया जिसने न्यायालय को रिपोर्ट दिया कि संस्था का आरोप सत्य है। याचकर्ता P.N. Bhagwati के आदेश दिया कि समुचित कदम उठाकर सरकार बंध्यना मजदूरों को मुक्त करे तथा मजदूरों की रक्षार्थ को सुधारे।

4) परमानंद ^{व्याप} बनाम भारत संघ (1989) : दुर्घटना में घायलों को बिना कागजी कार्रवाई के तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करें।

5) Environmental and consumer protection foundation इ.रा. 2007 ने PIL राजकोट में दाखा कि मथुरा एवं हृदावन के आसपास बड़ा जो की रिकार्ड पर एडवार्ट से रेकार का किया जिस CJJ बालकृष्णन ने 13 Dec 2007 को तीन सदस्यी पीठ ने फैसला दिया कि PIL को सुनवाई से नहीं रोक सकते हैं। 6 Dec 2007 को दो सदस्यी पीठ एके भास्कर एवं अश्वर ने PIL की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया।

2) जीने का अधिकार अनु० 21 - जेनका गांधी बनाम भारतसंघ (1988) के निर्णय के बाद न्यायालय ने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ का विस्तार करते हुए कहा कि "गरिमायुक्त जीवन" बताया। निम्नलिखित बातें हैं -

- 1 - मोहन जीन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) में निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक को 21 के अन्तर्गत लिया गया।
- 2 - सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश (1986) निःशुल्क कानूनी शिक्षा को अनु 21 के अन्तर्गत लिया गया।
- 3 - जयचंद नरार बनाम भारतसंघ में व्यापक व्यक्तियों को मुक्त शिक्षा 21 के अन्तर्गत 86 के संविधान संशोधन (2003) के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार 21-A के अन्तर्गत हुआ।

कार्यपालिका का स्वतंत्रिक विधि पालन

- 1 - देवाला कास में CBI को निर्देश दिया कि सीधे से को प्रकृतियों
- 2. 2006 में पेंस और गैर आवाजें
- 3 - आवाज आवाज को भी न्यायालय ने निर्देशित किया 2005 में वृत्तिका रूपमाल, हाकिमन सिंह स्टाजित
- 4 - वीरुड सिंह यादव लोकायुक्त.

7